

# मजदूर एकता लहर



हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार



ग़ंथ-37, अंक - 2

जनवरी 16-31, 2023

पाक्षिक अख़बार

कुल पृष्ठ-8

वर्ष 2022 में देशभर में मजदूरों और किसानों का संघर्ष :

## अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ़ संघर्ष में मजदूरों और किसानों की बढ़ती एकता

पिछले साल 2022 में निजीकरण के समाज-विरोधी और मजदूर-विरोधी कार्यक्रम के खिलाफ़ अनेक क्षेत्रों के मजदूर सड़कों पर पूरे साल संघर्ष में दिखाई दिए। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों एक सांझे मंच पर एक साथ आ रही हैं और निजीकरण के खिलाफ़ संघर्ष में एक-दूसरे को समर्थन दे रही हैं। 12 जून को महाराष्ट्र के पुणे में बिजली, बैंक और रेलवे के मजदूरों तथा शिक्षकों और अन्य क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं एवं जन संगठनों की एक संयुक्त मीटिंग हुई। जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी प्रकार के निजीकरण के खिलाफ़ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जायेगी।

बीमा, बैंक, रेलवे, बिजली आपूर्ति, सड़क परिवहन, एयरलाइंस, दूरसंचार और कोयला तथा इस्पात संयंत्र के मजदूरों, सफ़ाई मजदूरों, स्वास्थ्य सेवा के मजदूरों, शिक्षा क्षेत्र के मजदूरों, आशा व आंगनवाड़ी मजदूरों ने काम की बेहतर परिस्थितियों और बेहतर

वेतन के लिए तथा रोज़गार की असुरक्षा के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किये। उन्होंने ठेका प्रथा और मजदूर-विरोधी कानूनों का



विरोध किया। उन्होंने संगठित होने के अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया।

अपनी मांगों के एक संयुक्त मांगपत्र के समर्थन में 28-29 मार्च को देशव्यापी आम हड़ताल में करोड़ों मजदूरों ने भाग

लिया। सभी प्रकार की अड़चनों के बावजूद संघर्षरत मजदूरों ने हड़ताल की - जबकि कई जगहों पर उनके ऊपर आवश्यक सेवा

क़ानून (एस्मा) लगाया गया, कई जगहों पर उन्हें धमकियों और कुछ मामलों में पुलिस की मनमानी का सामना करना पड़ा। केरल में बी.पी.सी.एल. के मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर रोक लगाने

वाले उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश का सामना करना पड़ा।

देशभर में बैंक और बीमा कंपनियों के मजदूर तथा बाकी सभी कर्मचारी अपने दफ़तरों में नहीं गये। कोयला, स्टील, गैस व तेल संयंत्रों के मजदूरों, पावर ग्रिड, बिजली, तांबा उद्योग, बंदरगाह, दूरसंचार और सीमेंट क्षेत्र के मजदूरों ने 28 मार्च की सुबह से काम बंद कर दिया। महाराष्ट्र में बिजली मजदूरों और हरियाणा में सड़क परिवहन के मजदूरों ने राज्य सरकारों द्वारा एस्मा लगाए जाने के बावजूद इसका उल्लंघन करते हुये हड़ताल की। रेलवे और रक्षा क्षेत्र के मजदूरों ने देशभर में एक हज़ार से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन किए।

इस देशव्यापी हड़ताल में आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन तथा घरेलू मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी और कृषि मजदूर, फेरीवाले और दुकानदार, शामिल हुए। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में चक्का

शेष पृष्ठ 4 पर

## काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की हालतों पर संहिता : मजदूरों के अधिकारों का क्रूर हनन

मजदूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित मीटिंग

काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की हालतों पर संहिता (ओ.एस.एच.) उन चार श्रम संहिताओं में से एक है, जिसे हिन्दोस्तानी राज्य ने सितंबर 2020 में लागू किया था। इस संहिता ने इन्हीं मुद्दों से संबंधित, मौजूदा श्रम कानूनों को बदल दिया। हमारे देश के मजदूरों के कई दशकों के संघर्ष और बलिदान के बाद राज्य ऐसे कानूनों को पारित करने के लिए मजबूर हुआ, जिस कानून ने मजदूरों के कुछ हिस्सों को कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा देने का वादा किया है। मजदूरों का कहना है कि ओ.एस.एच. संहिता इन सभी उपलब्धियों पर हमला है। मजदूरों को काम की जगह पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की हालतों की जिन बदतर परिस्थितियों को पहले ही झेलना पड़ता था, इस संहिता ने उसे और भी विकट तथा खतरनाक बना दिया है। यह मजदूरों के जीवन और सम्मान के अधिकार का क्रूर हनन है। सभी ट्रेड यूनियनों, उद्योगों और सेवाओं से जुड़े मजदूरों तथा उनके संगठनों ने अपनी पार्टी की संबद्धता को दरकिनार करते हुये, इसका कड़ा विरोध किया है।

24 दिसंबर, 2022 को मजदूर एकता कमेटी ने ओ.एस.एच. संहिता पर मीटिंग आयोजित की जिसे संबोधित करते हुए, वक्ताओं ने रेलवे, निर्माण स्थलों, कपड़ा व वस्त्र उद्योग, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों, घरेलू कामगारों और कई अन्य क्षेत्रों व सेवाओं से जुड़े मजदूरों की काम करने की खतरनाक परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया।

मीटिंग में मुख्य वक्ता थे - मजदूर एकता कमेटी के सचिव श्री बिरजू नायक; ऑल इंडिया रेलवे ट्रेड मेटेनर्स यूनियन (ए.आई. आर.टी.यू.) के राष्ट्रीय महासचिव श्री कांता राजू; भारतीय रेलवे लोको रनिंगमेन संगठन के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय पांथी; निर्माण मजदूर पंचायत संगम के सचिव श्री सुभाष भटनागर और सेवाशक्ति हेल्थकेयर कंसल्टेंसी की संस्थापक डॉ. स्वाति राणे। मीटिंग का संचालन मजदूर एकता कमेटी की ओर से सुचरिता ने किया।

श्री बिरजू नायक ने बताया कि मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति हमेशा से ही हमारे देश के मजदूर वर्ग की प्रमुख चिंता रही है। काम की जगह पर हर साल लाखों मजदूर अपनी जान गंवाते हैं। लाखों लोग घायल हो

जाते हैं, उनमें से कई जीवनभर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। फैक्ट्रियों में आग लगना, भूमिगत खदानों का गिरना और उनमें मजदूरों का फंसना, खदानों में पानी भर जाना और मजदूरों का डूब जाना, भट्टियों में विस्फोट होना, निर्माण स्थलों पर मजदूरों का गिरना, काम के दौरान ट्रेकमैन की मौत, सीवर की सफ़ाई के दौरान मौतें, ये सब दुखद घटनाएं हमारे देश में रोजमर्रा की बात हैं - इनमें से कुछ ही के बारे में रिपोर्ट्स भी मिलती हैं, परन्तु अधिकांश की रिपोर्ट तक नहीं की जाती। इस तरह अपनी जान गंवाने वाले अधिकांश मजदूर ठेके पर काम करने वाले होते हैं। सुरक्षा के सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, मजदूरों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। काम की जगहों पर होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या के लिये कोई भी आधिकारिक गिनती नहीं की जाती। क्योंकि सरकार को हमारे देश के लाखों अपंजीकृत कारखानों, कार्यालयों, दुकानों, स्वेटशॉप और निर्माण स्थलों में काम करने वाले मजदूरों की हालतों पर नज़र रखने की कोई परवाह नहीं है।

काम की जगहों पर मजदूरों की मौतों और उनको लगी चोटों को एक दुर्घटना कह दिया जाता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि इस सच्चाई को छिपाया जाता है कि यह सब तो पूंजीपति मालिकों द्वारा सुरक्षा उपायों की जानबूझकर की गई उपेक्षा का नतीजा है। अपने मुनाफ़ों को अधिकतम करने की लालच को पूरा करने के लिए, मालिक इसे जायज़ मानते हैं।

बिरजू नायक ने समझाया कि काम की जगह पर होने वाली मौतों का एकमात्र

शेष पृष्ठ 7 पर

### अंदर पढ़ें

■ सोवियत संघ के गठन की शताब्दी	2
■ दुनियाभर के मजदूर वर्ग और लोगों के संघर्ष	3
■ ब्रिटेन के मजदूरों का संघर्ष	3
■ बिजली का निजीकरण	5
■ पेट्रोलियम और गैस मजदूरों ने संघर्ष तेज़ किया	6
■ पाठकों की प्रतिक्रिया	6







To .....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई-392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक-मधुसूदन कस्तूरी, ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020 email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911



WhatsApp  
9868811998

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :  
ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

## घरों से बेदखल किये जाने के खिलाफ हल्लानी के लोगों का विशाल विरोध प्रदर्शन

उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने घरों से जबरन बेदखल करने की धमकी के खिलाफ लोगों का अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हल्लानी में चल रहा है। 20 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बनभूलपुरा में 78 एकड़ भूमि, जिसके लिये रेलवे द्वारा दावा किया गया था, से हजारों परिवारों को बेदखल करने के लिए बल प्रयोग किया जाये। इस आदेश के बाद यह विरोध शुरू हुआ। अदालत ने राज्य से कहा कि वह लोगों को उनके घरों से बेदखल करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करे। इसके बाद, उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ 7 दिनों का समय देते हुए, 1 जनवरी, 2023 को बेदखली का एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें लोगों को अपना सामान हटाने और अपने घरों को खाली करके छोड़ देने के लिए कहा गया था।

लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया। कड़ाके की ठंड में पचास हजार महिला, पुरुष और बच्चे अपने घरों पर अपना हक जताते हुए, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस संघर्ष के मद्देनजर सर्वोच्च अदालत ने लोगों को बेदखल करने के उच्च अदालत के आदेश पर, 5 जनवरी को रोक लगाने का फैसला सुनाया।

रेलवे ने दावा किया है कि बनभूलपुरा की यह ज़मीन उसकी है, लेकिन इस ज़मीन पर भारतीय रेल का मालिकाना हक है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। बेदखली के खतरे का सामना करने वाले बहुत से लोग इस बस्ती में 5 दशकों से भी अधिक समय से रह रहे हैं। लोगों के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो साबित करते हैं कि वे 1947 से इस क्षेत्र में संपत्ति के मालिक



हैं। फिर भी हिन्दोस्तानी राज्य और रेलवे, लोगों को अपनी बस्ती से बेदखल करने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं?

भारतीय रेल का निजीकरण भी हिन्दोस्तानी राज्य के उस अभियान में निहित है, इसका सबसे हाल का उदाहरण है राष्ट्रीय मुद्दीकरण पाइपलाइन। सरकार ने अन्य चीजों के साथ-साथ रेलवे के 200 स्टेशनों का विकास करने और उनके

रखरखाव के लिए पूंजीपतियों को सौंपने के अपने फैसले की घोषणा की है। भारतीय रेल ने पूरे देश में अपनी मालिकी वाली प्रमुख भूमि के बारे में फैसले लेने के लिए एक 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण' की स्थापना की है।

उत्तर पूर्व रेलवे का काठगोदाम स्टेशन, जो कि हल्लानी में है, यह उन निर्धारित स्टेशनों में से एक है जिसे विकास और रखरखाव के लिए सरकार ने पूंजीपतियों को



सौंपने का फैसला किया है। यह उत्तराखंड को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों में से एक है। बनभूलपुरा बस्ती काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास है। इस बात की पूरी संभावना है कि उत्तराखंड सरकार और पूर्वोत्तर रेलवे, इस क्षेत्र में कई दशकों से रह रहे लोगों को इसलिये बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि इस ज़मीन की मांग उन निजी पूंजीपतियों ने की हो, जिन्हें काठगोदाम रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की ज़मीनें सौंपी जा रही हैं।

हिन्दोस्तानी राज्य के क़ानून किसी न किसी बहाने से लोगों की ज़मीन को हड़पने और फिर उस ज़मीन को बड़े पूंजीपतियों को सौंपने में सक्षम हैं। पूरे देश में लोगों का यह अनुभव है कि ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए राज्य द्वारा पूरी कालोनियों को गिरा दिया जाता है, जिनमें दशकों से लोग रह रहे हैं। पीड़ितों को लोगों का समर्थन न मिले, इसलिये राज्य लगातार यह प्रचार करता है कि जिनके घर गिराए जा रहे हैं वे 'अवैध' रूप से रह रहे हैं।

अपने घरों से बेदखली के खिलाफ हल्लानी के लोगों का संघर्ष, देशभर के लाखों मेहनतकशों के उसी संघर्ष का हिस्सा है, जिसने सिर पर विध्वंस की तलवार लटक रही है। विभिन्न शहरों में मेट्रो लाइनों के पास रहने वाले, रेलवे स्टेशनों के पास रहने वाले और रेलवे लाइनों के पास रहने वाले लोगों को विध्वंस का सामना करना पड़ता है। पूंजीपतियों को रेलवे स्टेशनों और अन्य संपत्तियों को बेचने के हिन्दोस्तानी राज्य के अभियान का डटकर विरोध करने की ज़रूरत है।

<http://hindi.cgpi.org/22989>

### मज़दूर एकता कमेटी की मीटिंग ...

#### पृष्ठ 7 का शेष

दिए जाते। वे बंधुआ मज़दूर की तरह काम करती हैं। अधिकांश मज़दूरों को ई.एस.आई. सी. की सुविधाएँ नहीं मिलती। बीमारी से ठीक होने के लिये, दुर्घटनाओं के लिये, ली गई छुट्टी या अन्य किसी छुट्टी के लिए कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाता। कृष्णमूर्ति ने कहा कि ओ.एस.एच. संहिता, मज़दूरों के मूल अधिकारों पर खुल्लम-खुल्ला हमला है। उन्होंने सभी मज़दूर संगठनों से श्रम संहिताओं को रद्द करवाने के लिए एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया।

कामगार एकता कमेटी के जी. भावे ने बताया कि रेलवे इंजन चालकों और ट्रेकमैनो के काम के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं। यह न केवल उनके काम को और खतरनाक बना रहा है बल्कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और यात्रियों के लिए भी जोखिम बढ़ा रहा है।

यूके के इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के दलविंदर ने बताया कि सभी सरकारें लोगों से वादे करती हैं, लेकिन पूंजीपति वर्ग के एजेंडे को ही लागू करती हैं। लोगों को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है ताकि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहरा सकें, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने और बहस करने की ज़रूरत है।

वक्ताओं ने मज़दूर एकता कमेटी को मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया, जहां विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूर अपनी समस्याओं के बारे में अन्य क्षेत्रों के मज़दूरों से बात कर सकते हैं, जिससे मज़दूर वर्ग की एकता मजबूत हो सके।

सभी इस बात पर एकमत थे कि चार श्रम संहिताओं का उद्देश्य मज़दूरों के शोषण को तेज़ करना है। ओ.एस.एच. संहिता काम की जगह पर मज़दूरों की असुरक्षा बढ़ा रहा है और वर्षों के संघर्ष से जीते गए अधिकारों से मज़दूरों को

वंचित कर रहा है। मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए, इन श्रम संहिताओं के खिलाफ एकजुट संघर्ष को तेज़ करने की आवश्यकता है।

मज़दूर वर्ग के लिए आगे का रास्ता है पूंजीपति वर्ग खिलाफ और हमारे अधिकारों पर हो रहे सभी हमलों के खिलाफ अपनी एकता को और मजबूत करना। हमें उदारिकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के

कार्यक्रम के खिलाफ मज़दूरों-किसानों की एकता को मजबूत करना होगा। हमें मज़दूरों और किसानों के राज की स्थापना के उद्देश्य से अपने संघर्ष को तेज़ करने की ज़रूरत है, ताकि पूंजीवादी लालच को पूरा करने की बजाय मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी जा सके।

<http://hindi.cgpi.org/22973>

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्कैन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम-लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी

खाता संख्या-20066800626,

ब्रांच नं.-00974, IFSCCode: MAHB0000974, मो.-9810167911

वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998

email: mazdoorektalehar@gmail.com

